**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *204**

**01 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए**

**इस्पात कंपनियों द्वारा आस्थगित अदायगी**

***204. श्री जी. हरि:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत सहित विश्व स्तर पर इस्पात क्षेत्र में आई गिरावट पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार लगातार मंदी के कारण वित्तीय तंगी का सामना कर रही नकदी की कमी वाली इस्पात कंपनियों के लिए अदायगी तंत्र को और अधिक शिथिल बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई इस्पात कंपनियों ने इस संबंध में सरकार से सम्पर्क किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) देश में इस्पात की मांग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात मंत्री** **(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)**

(क) से (घ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

***

**"इस्पात कंपनियों द्वारा आस्थगित अदायगी" के बारे में श्री जी. हरि, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 01 अगस्त, 2016 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *204 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

(क): जी हॉ। भारतीय इस्पात उद्योग इस समय वैश्विक क्षमता अधिक होने के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है जिसके फलस्वरूप प्रमुख इस्पात उत्पादक देश भारत में अपने उत्पादों की बिक्री अपनी उत्पादन लागत से भी कम कीमतों पर कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादकों को कीमतों में काफी कमी करनी पड़ी है जिससे उनका लाभ मार्जिन कम हुआ है।

(ख) और (ग): इस्पात उद्योग की सहायता के लिए उपयुक्त पैकेज दिए जाने पर विचार करने के लिए इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स तथा इण्डियन स्टील एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आन्तरिक एवं बाहरी कारकों से प्रभावित व्यवहार्य इकाइयों के ऋणों की पुनर्संरचना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवसंरचना और मुख्य उद्योगों के वर्तमान दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लोचशील संरचना के संबंध में भी दिशानिर्देश जारी किए है। बैंक कारपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग मेकैनिज्म का भी सहारा लेते हैं। उपर्युक्त प्रावधान वित्तीय दबाव का सामना करने वाले इस्पात उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं।

(घ): भारतीय इस्पात क्षेत्र में विकास की पर्याप्त संभावना इस तथ्य से रेखांकित होती है कि देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 61 किग्रा. है जो कि 208 किग्रा. वैश्विक औसत से काफी कम है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवसंरचना के लिए दो लाख करोड़ रूपए से अधिक के बजट आबंटन से भी इस्पात उद्योग को लाभ होने की आशा है, जिससे इस्पात की मांग बढ़ेगी।

***